Title: Requests the Central Government to intervene to resolve the Contracts of the Diamond Mines in Madhya Pradesh.

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दुनिया की प्रसिध्द हीरा खदान है। अब उस पर दक्षिण अफ्रीका की कम्पनी डीबियर्स की नजर लगी हुई है और लगातार चार साल से मध्य प्रदेश सरकार यह कोशिश कर रही है कि वह सारा ठेका, सारा प्रोस्पैक्टिग का कार्य, उत्खनन का कार्य डीयर्स को मिल जाये, लेकिन जब वह इसमे सफल नहीं हुई तो पिछले दरवाजे से वह हीरा खदान में प्रोस्पैक्टिग के लिए और दूसरे प्रकार के कार्य के लिए उन्होंने मुंबई की एक फर्म को देने का फैसला किया है, जो वास्तव में अनुचित हैं, एक व्यक्ति को लाभ देने का प्रयास है, जबकि वह रिजर्व फोरेस्ट है। वह हीरा खदान भारतीय वन संरक्षण अधिनियम,१९८०के तहत वहां पर अभी क्लयरेंस नहीं है, इसलिए भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर तत्काल हस्तक्षेप करें, क्योंकि एक नये राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य बनना तय हुआ है। केन्द्र सरकार इसके लिए प्रतिवध्द है तो नये राज्य के बाद उस हीरा खदान के बारे में फैसला किया जाये, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

...(व्यवधान)